

ई सदेश

08 अक्टूबर, 2026 | अंक - 226

सात दिन, सात पृष्ठ



- ▶ वैचारिक चिंतन, वीरता और तकनीक के समन्वय से प्रदेश में सुरक्षित वातावरण: मुख्यमंत्री
- ▶ बापू और शास्त्री जी के आदर्शों से सशक्त हो रहा आत्मनिर्भर और विकसित भारत: मुख्यमंत्री
- ▶ धन के अभाव में कोई छात्र शिक्षा से वंचित न रहे, छात्रवृत्ति व्यवस्था को बनाया पारदर्शी: मुख्यमंत्री
- ▶ भदोही, मिर्जापुर व वाराणसी को सिल्क क्लस्टर के रूप में विकसित करेगी सरकार: मुख्यमंत्री
- ▶ विकास और विरासत के समन्वय से वैश्विक पटल पर स्थापित हो रहा भदोही: मुख्यमंत्री
- ▶ लखनऊ को देश की अग्रणी एआई इनोवेशन सिटी बनाएगी प्रदेश सरकार: मुख्यमंत्री
- ▶ काशी में 'आबे मेमोरियल कॉरिडोर' का लोकार्पण: भारत-जापान प्रगाढ़ मित्रता का जीवंत प्रतीक

वैचारिक चिंतन, वीरता और तकनीक के समन्वय से प्रदेश में सुरक्षित वातावरण: मुख्यमंत्री



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 01 अक्टूबर, 2026 को लखनऊ में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 87 अत्याधुनिक इण्टरसेप्टर वाहनों (25 चारपहिया एवं 62 दोपहिया) को फ्लैग ऑफ किया। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री प्रकाश सिंह की पुस्तक 'संघर्ष' का विमोचन किया तथा पुलिस के 16 अधिकारियों व कर्मियों को राष्ट्रपति वीरता पदक और 10 को मुख्यमंत्री वीरता पदक प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही, उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस को पहली बार मिले कीर्ति चक्र से सम्मानित अमर शहीद निरीक्षक श्री सुनील कुमार की धर्मपत्नी को भी सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज का यह आयोजन वैचारिक चिंतन, वीरता और तकनीक—तीनों महत्वपूर्ण आयामों का अनुपम समन्वय प्रस्तुत करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी समाज में स्वस्थ चिंतन और समृद्धि की परिकल्पना तभी साकार हो सकती

है, जब वहां पूर्ण सुरक्षा का वातावरण उपलब्ध हो। उत्तर प्रदेश पुलिस का मूल मंत्र 'आपकी सुरक्षा, हमारा संकल्प' है और राज्य सरकार अपराध व अपराधियों के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति पर पूरी निष्ठा से अडिग है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वर्ष 2017 से पूर्व राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के चलते प्रदेश में कानून-व्यवस्था की बदतर स्थिति थी, समानांतर माफिया राज चलता था और पुलिस व्यवस्था जर्जर थी। वर्ष 2017 के बाद पुलिस सुधारों को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश में 7 पुलिस कमिश्नरेट स्थापित किए गए। तकनीक आधारित स्मार्ट पुलिसिंग को गति देते हुए प्रदेश के प्रमुख शहरों में 14 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे तथा जनपदों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) स्थापित किए गए हैं, जिससे 'सेफ सिटी' की संकल्पना धरातल पर उतरी है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में प्रतिवर्ष 23,000 से 24,000 लोगों की सड़क

दुर्घटनाओं में असामयिक मृत्यु एक गंभीर सामाजिक व प्रशासनिक चुनौती है। तकनीक के समन्वित उपयोग से इन दुर्घटनाओं को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आज फ्लैग ऑफ किए गए आधुनिक इण्टरसेप्टर वाहन दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में तैनात होकर सड़क सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराएंगे और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाएंगे।

मुख्यमंत्री जी ने पूर्व डीजीपी श्री प्रकाश सिंह के 35 वर्षों के सेवा अनुभवों पर आधारित पुस्तक 'संघर्ष' की सराहना करते हुए कहा कि यह केवल विचारों का संकलन नहीं, बल्कि जटिल व्यावहारिक चुनौतियों का प्रेरणादायी दस्तावेज है। उन्होंने रेखांकित किया कि मंच पर पूर्व और वर्तमान पुलिस महानिदेशक की एक साथ उपस्थिति उत्तर प्रदेश पुलिस के पुराने व नए अनुभवों की निरंतरता और प्रगतिशील समन्वय का सशक्त प्रतीक है।



बापू और शास्त्री जी के आदर्शों से सशक्त हो रहा आत्मनिर्भर और विकसित भारत: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 02 अक्टूबर, 2026 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 157वीं पावन जयन्ती तथा देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व० लाल बहादुर शास्त्री जी की 122वीं जयन्ती के अवसर पर राजधानी लखनऊ में दोनों विभूतियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री जी ने जी०पी०ओ० स्थित गांधी प्रतिमा, हजरतगंज स्थित क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री भवन पहुंचकर दोनों महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने गांधी आश्रम में चरखा चलाया तथा खादी वस्त्रों का क्रय भी किया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वाणी में वास्तविक प्रभाव और शक्ति तभी आती है, जब व्यक्ति के आचार और विचार में पूर्ण समन्वय हो। पूज्य बापू और शास्त्री जी ने जो कहा, उसे अपने आचरण में पूरी निष्ठा से उतारकर दिखाया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष से लेकर भारत के स्वाधीनता संग्राम तक लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण मार्ग अपनाकर इसे एक जनांदोलन बनाया। बापू ने चरखे को मात्र वस्त्र निर्माण का माध्यम नहीं, बल्कि स्वावलम्बन, आत्मसम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता का सशक्त प्रतीक बनाया था।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि राज्य सरकार ने गांधी जयन्ती के उपलक्ष्य में खादी वस्त्रों पर 30 जनवरी, 2027 तक 25 प्रतिशत की विशेष छूट उपलब्ध कराई है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे खादी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर स्थानीय कारीगरों, हस्तशिल्पियों और बुनकरों के हुनर को

सम्मान दें। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 'स्वच्छ भारत अभियान' के जरिए 12 करोड़ से अधिक परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराकर नारी गरिमा और स्वच्छता की मिसाल कायम की गई है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बापू के स्वदेशी दर्शन को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में 'एक जनपद, एक उत्पाद' (ओ०डी०ओ०पी०) योजना के माध्यम से स्थानीय शिल्पों को वैश्विक पहचान दिलाई जा रही है। 'लोकल को ग्लोबल' बनाने की यह पहल ही आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी के 'ग्राम स्वराज' के सपने को साकार करने हेतु गांवों में स्थापित ग्राम सचिवालयों के जरिए ग्रामीणों को तकनीक की मदद से उनके द्वार पर नागरिक सुविधाएं मिल रही हैं और स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन सादगी, शुचिता, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र-समर्पण की अनूठी मिसाल है। वर्ष 1965 में शास्त्री जी द्वारा दिया गया 'जय जवान, जय किसान' का उद्घोष स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय जीवन मंत्र बना। इसी दृढ़ संकल्प का परिणाम है कि सीमाओं पर सजग जवान देश की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा सुदृढ़ कर रहे हैं, वहीं अन्नदाता किसान के अथक परिश्रम से पूर्व में दूसरे देशों पर निर्भर रहने वाला भारत आज न केवल 140 करोड़ देशवासियों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उपजा रहा है, बल्कि दुनिया के अनेक देशों की आवश्यकताओं को भी पूरा करने में पूर्ण सक्षम है।



धन के अभाव में कोई छात्र शिक्षा से वंचित न रहे, छात्रवृत्ति व्यवस्था को बनाया पारदर्शी: मुख्यमंत्री



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 03 अक्टूबर, 2026 को लखनऊ में आयोजित छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम में अल्प आय वर्ग के पूर्वदशम् (कक्षा 9-10) एवं दशमोत्तर कक्षाओं के 4.60 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 148 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि सीधे अंतरित की। इस अवसर पर उन्होंने छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश के 70 लाख विद्यार्थियों तक छात्रवृत्ति का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है तथा आगामी 26 जनवरी तक सभी पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में धनराशि हर हाल में प्रेषित कर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि छात्रवृत्ति केवल आर्थिक सहायता की शुरुआत नहीं है, बल्कि गरीब व जरूरतमंद परिवारों के बच्चों के सपनों को साकार करने का सशक्त माध्यम है, ताकि धन की कमी किसी की पढ़ाई में रुकावट न बने। उन्होंने बताया कि पहले छात्रवृत्ति व्यवस्था में भारी विसंगतियां थीं, लेकिन वर्तमान सरकार ने डीबीटी और जीरो बैलेंस बैंक खातों के माध्यम से इसे पूर्णतः पारदर्शी बनाया है, जिससे स्वीकृत धनराशि सीधे छात्रों तक पहुंच रही है। प्रदेश में छात्रवृत्ति का बजट पूर्ववर्ती 2,900 करोड़ रुपये से बढ़ाकर

6,200 करोड़ रुपये से अधिक किया गया है तथा छात्रों की सुविधा हेतु वर्ष में दो बार छात्रवृत्ति वितरण की व्यवस्था लागू की गई है।

मुख्यमंत्री जी ने समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को कड़े निर्देश दिए कि पोर्टल के माध्यम से डेटा फीडिंग कार्य त्वरित गति से पूरा किया जाए ताकि तकनीकी अथवा संस्थागत त्रुटि के कारण कोई भी पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 से पूर्व बेसिक शिक्षा में 19 से 20 प्रतिशत ड्रॉपआउट रेट था, जिसे 'ऑपरेशन कायाकल्प' के तहत बालक-बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय, शुद्ध पेयजल, फर्नीचर और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं विकसित कर दूर किया गया। प्रदेश में 18 कमिश्नरी स्तर पर अटल आवासीय विद्यालय, 746 विकास खंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा 'प्रोजेक्ट अलंकार' के अंतर्गत 2,300 से अधिक इंटर कॉलेजों का जीर्णोद्धार कराया गया है। साथ ही यूपी बोर्ड परीक्षाओं और परिणामों को 15-15 दिनों में संपन्न कराकर शैक्षणिक सत्र को नियमित किया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि प्रदेश सरकार युवाओं को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ रोजगार के भरपूर अवसर उपलब्ध कराने हेतु निरंतर कटिबद्ध है। अब तक लगभग 10 लाख

युवाओं को निष्पक्ष सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं और आगामी 6 माह में 1 लाख अतिरिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 'मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग' संचालित है तथा 2 करोड़ युवाओं को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के क्रम में अब तक 60 लाख टैबलेट/स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं। बेटियों के सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 25,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है तथा अगले माह स्नातक अंतिम वर्ष की लगभग 50,000 मेधावी छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज का उत्तर प्रदेश दंगों और कर्फ्यू के साए से पूरी तरह मुक्त होकर 'नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा' के वातावरण के साथ देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने विद्यार्थियों से वर्ष 2047 के 'विकसित भारत' के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। मुख्यमंत्री जी ने छात्रों को प्रेरित किया कि वे छात्रवृत्ति राशि का सदुपयोग अच्छी संदर्भ पुस्तकें खरीदने और ज्ञान संवर्धन में करें तथा राष्ट्र निर्माण में अपने दायित्वों का निर्वहन करें।



भदोही, मिर्जापुर व वाराणसी को सिल्क क्लस्टर के रूप में विकसित करेगी सरकार: मुख्यमंत्री



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 04 अक्टूबर, 2026 को जनपद भदोही में अन्तरराष्ट्रीय हस्तनिर्मित कालीन व्यापार मेला 'इण्डिया कार्पेट एक्सपो' के स्वर्ण जयंती संस्करण का शुभारम्भ किया तथा प्रदर्शनी का अवलोकन कर निर्यातकों व उद्यमियों से संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (ओडीओपी) के तहत कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के बाद अब सरकार वाराणसी-विन्ध्य रीजनल डेवलपमेंट प्लान के तहत जनपद संत रविदास नगर (भदोही), मिर्जापुर और वाराणसी को वृहद 'सिल्क क्लस्टर' के रूप में विकसित करने जा रही है। इसके माध्यम से स्थानीय उत्पादों को विशिष्ट डिजाइन, उन्नत तकनीक और वैश्विक बाजार से सुव्यवस्थित ढंग से जोड़ा जाएगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश के कुल कालीन निर्यात में इस परिक्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत है और अकेले भदोही से वर्तमान में 6,100 करोड़ रुपये का निर्यात हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष एक्सपो में 227 से अधिक प्रदर्शक तथा ब्रिक्स देशों सहित 65 राष्ट्रों के 450 से अधिक विदेशी खरीदार भाग ले रहे हैं,

जो यह साबित करता है कि प्रदेश के हस्तशिल्प ने वैश्विक पटल पर अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने गर्व व्यक्त किया कि नए संसद भवन की शोभा बढ़ाने वाले कालीन भी भदोही के कुशल कारीगरों की साधना का अनुपम उदाहरण हैं। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि अकेले संत रविदास नगर (भदोही) में लगभग 2,500 एमएसएमई इकाइयां संचालित हैं, जिनका वार्षिक टर्नओवर 10 हजार करोड़ रुपये है और यह उद्योग 5 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करा रहा है। यहां के जीआई टैग प्राप्त हैंडमेड कार्पेट का निर्यात अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन जैसे प्रमुख देशों में हो रहा है। उन्होंने कहा कि कालीन उद्योग की सबसे बड़ी ताकत यहां की महिलाओं की सक्रिय भागीदारी है, जो घर-परिवार के साथ-साथ इस पारंपरिक विधा से जुड़कर परिवार की आय बढ़ाने और उद्योग को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में सुदृढ़ कानून-व्यवस्था और औद्योगिक नीतियों के फलस्वरूप 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश

प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उद्योग की मांग के अनुरूप युवाओं को कुशल बनाने हेतु हर जनपद में 'सरदार वल्लभ भाई पटेल इम्प्लॉयमेंट एण्ड इण्डस्ट्रियल जोन' तथा लखनऊ-हरदोई में 1,000 एकड़ में 'पीएम मित्र पार्क' विकसित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भदोही स्थित 'इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्पेट टेक्नोलॉजी' तकनीकी शिक्षा, डिजाइनिंग व डाइंग प्रशिक्षण के माध्यम से उद्योग को नई गति दे रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कार्पेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल (सीईपीसी) और संबंधित संस्थाओं को निर्देशित किया कि वे नारी शक्ति वंदन अधिनियम की भावना के अनुरूप कालीन उद्योग में महिलाओं की भागीदारी को केवल श्रमिक तक सीमित न रखकर उन्हें सक्रिय उद्यमी व नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे लाएं। उन्होंने अनुभवी कारीगरों की अमूल्य कला को नई पीढ़ी के प्रशिक्षण से जोड़ने का भी आह्वान किया, ताकि पारम्परिक धरोहर को आधुनिक तकनीक व वैश्विक बाजार की मांग के अनुरूप सतत और सशक्त बनाए रखा जा सके।



विकास और विरासत के समन्वय से वैश्विक पटल पर स्थापित हो रहा भदोही: मुख्यमंत्री



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 04 अक्टूबर, 2026 को जनपद भदोही के भदोही, औराई एवं ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित 1,340 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 112 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, आवास व कृषि यंत्रों की चाभियां, नवनियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को नियुक्ति पत्र तथा आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड वितरित किए। उन्होंने बच्चों का अन्नप्राशन और गर्भवती महिलाओं की गोदभराई भी कराई।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भदोही आज अपनी सदियों पुरानी कालीन शिल्पकला के साथ-साथ विकास, विरासत, पर्यटन, शिक्षा और वैश्विक व्यापार के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। संत रविदास जी के सामाजिक समरसता के संदेश का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बिना किसी भेदभाव के 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को निःशुल्क राशन और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। 'सबका साथ, सबका विकास' के संकल्प के साथ सरकार हर गरीब, युवा, महिला और श्रमिक के जीवन को खुशहाल बना रही है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जनपद के पीजी कॉलेज को उच्चकृत कर 'काशी नरेश विश्वविद्यालय' का स्वरूप दिया गया है, जिससे जिले के सभी डिग्री कॉलेज संबद्ध हो चुके हैं और अब युवाओं को यहीं से डिग्री प्राप्त होगी। साथ ही जनपद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की प्रक्रिया भी तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पहले 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया' का दौर था, जिसे समाप्त कर

वर्तमान सरकार ने 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज', 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' और अब 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन कुज़ीन' की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1,340 करोड़ रुपये की परियोजनाओं में 151 करोड़ रुपये के विद्युत उपकेंद्र, प्रमुख मार्गों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण, ज्ञानपुर बस स्टेशन का पुनर्निर्माण और पुलिस बैरक का लोकार्पण शामिल है। वहीं, सीतामढ़ी-धनतुलसी-डेंगरपुर घाट पर गंगा नदी पर दीर्घ सेतु, भदोही अमृत-2.0 पेयजल योजना, जिला जेल निर्माण तथा माधोसिंह रेलवे फ्लाईओवर (डीपीआर पूर्ण) जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को नई मजबूती प्रदान करेंगी। इसके अतिरिक्त सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी, बाबा सेमराजनाथ धाम, गोपीगंज स्थित ज्ञानानंद मंदिर के गंगा घाटों और चकवा महादेव जैसे पौराणिक तीर्थस्थलों का कायाकल्प कर पर्यटन सर्किट को सुदृढ़ किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि भदोही में आयोजित इंडिया कार्पेट एक्सपो में 65 देशों के 450 से अधिक विदेशी खरीदारों (जिनमें ब्रिक्स देशों के 106 बायर्स शामिल हैं) और 250 एग्जिबिटर्स की उपस्थिति स्थानीय हस्तशिल्प की वैश्विक मांग का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब बॉटम थ्री से निकलकर देश के टॉप थ्री राज्यों में अग्रणी बन चुका है। प्रदेश में युवाओं को रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं; साढ़े नौ लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं तथा आगामी 6 माह में 1 लाख युवाओं को निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के जरिए सरकारी सेवा में अवसर प्रदान किए जाएंगे।



लखनऊ को देश की अग्रणी एआई इनोवेशन सिटी बनाएगी प्रदेश सरकार: मुख्यमंत्री



उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 06 अक्टूबर, 2026 को एचसीएल टेक के एचसीएल आईटी सिटी लखनऊ के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए युवाओं से लखनऊ को आगामी 05 वर्षों में देश की अग्रणी एआई इनोवेशन सिटी के रूप में स्थापित करने का आह्वान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने फेज-2 के तहत विस्तारीकरण कार्य का शिलान्यास करने के साथ ही 'इमर्जिंग टेक स्किलिंग सेण्टर' का लोकार्पण किया तथा एचसीएल के अधिकारियों एवं कर्मियों से सीधा संवाद भी स्थापित किया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार लखनऊ में 50 विश्वस्तरीय एआई स्टार्ट-अप्स की स्थापना, उनके संवर्धन और वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत नवाचार ईको-सिस्टम तैयार करने हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने युवाओं को प्रधानमंत्री जी के 'विकसित भारत' विजन से जुड़ने की प्रेरणा देते हुए कहा कि आगामी 21 वर्षों में देश को अग्रणी पायदान पर ले जाने में युवा मेधा की केंद्रीय भूमिका होगी।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि पांच दशक पूर्व श्री शिव नाडर द्वारा उत्तर प्रदेश की पावन धरा

से शुरू की गई एचसीएल की यात्रा आज एक वैश्विक पहचान हासिल कर चुकी है। उन्होंने इस बात पर हर्ष व्यक्त किया कि 100 युवाओं से शुरू हुआ लखनऊ कैम्पस आज 12,000 युवाओं के साथ एचसीएल का सबसे बड़ा कैम्पस बन चुका है, जिसने राज्य के युवाओं के दिल्ली, मुंबई और बंगलुरु जैसे महानगरों में होने वाले पलायन पर प्रभावी विराम लगाया है।

मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि सुदृढ़ कानून-व्यवस्था और सुरक्षित परिवेश के चलते आज प्रदेश में बेटियां बेझिझक नाइट शिफ्ट में कार्य कर रही हैं तथा विगत 09 वर्षों में 10 लाख युवाओं को पारदर्शी ढंग से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि आज का उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे नेटवर्क, बेहतर कनेक्टिविटी और सुरक्षा के वैश्विक मानकों के लिए पहचाना जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री जी के 'डिजिटल इण्डिया' और डीबीटी मॉडल ने गरीब कल्याण की योजनाओं को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने का कार्य किया है। इसी क्रम में एचसीएल फाउंडेशन ने भी तकनीकी विस्तार के साथ-साथ सीतापुर व

बुलंदशहर सहित राज्य के 3,000 से अधिक गांवों के 50 लाख लोगों तक शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला स्वावलंबन के माध्यम से समावेशी विकास को गति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री जी ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि देश के 55 प्रतिशत मोबाइल और 60 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का निर्माण अकेले उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसके साथ ही प्रदेश का आईटी व आईटीईएस निर्यात 01 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है, जिसे आगामी 04 वर्षों में 2.5 लाख करोड़ रुपये तथा इलेक्ट्रॉनिक निर्यात को 2030 तक 02 लाख करोड़ रुपये पहुंचाने का संकल्प लिया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि सॉफ्टवेयर और तकनीकी विकास को केवल एनसीआर तक सीमित न रखते हुए प्रदेश के अन्य अंचलों में भी विस्तारित किया जाए। वर्तमान में प्रदेश में 07 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कार्यरत हैं, जबकि वाराणसी, बरेली, कानपुर व गोरखपुर में नए पार्क विकसित किए जा रहे हैं। नई स्टार्ट-अप नीति के तहत नोएडा और लखनऊ को डीप टेक हब तथा लखनऊ को देश की प्रथम एआई सिटी के रूप में तेजी से स्थापित किया जा रहा है।



काशी में 'आबे मेमोरियल कॉरिडोर' का लोकार्पण: भारत-जापान प्रगाढ़ मित्रता का जीवंत प्रतीक



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 07 अक्टूबर, 2026 को वाराणसी स्थित रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री स्व० शिंजो आबे की स्मृति को समर्पित 'आबे मेमोरियल कॉरिडोर' का उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अकी आबे के साथ संयुक्त रूप से लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह स्मृति गलियारा स्व० शिंजो आबे के भारत-जापान संबंधों को सुदृढ़ करने में दिए गए ऐतिहासिक योगदान का प्रतीक है तथा प्रदेश की 25 करोड़ जनता, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और समस्त देशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि आज से ठीक 25 वर्ष पूर्व, 07 अक्टूबर, 2001 को श्री नरेन्द्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उसी दौर में स्व० शिंजो आबे के साथ उनकी अटूट मित्रता की नींव पड़ी थी, जो पद नहीं बल्कि परस्पर विश्वास पर आधारित रही। उन्होंने कहा कि वर्ष 2007 में दोनों नेताओं की पहली भेंट हुई और शिंजो आबे ने भारतीय संसद में कहा था कि मजबूत भारत जापान के और मजबूत जापान भारत के सर्वोत्तम हित में है। वर्ष 2014 में काशी-क्योटो समझौता, 2015 में आबे जी

की गंगा आरती यात्रा, 2017 में बुलेट ट्रेन परियोजना का शिलान्यास तथा 2021 में उन्हें 'पद्म विभूषण' से अलंकृत किया जाना इसी प्रगाढ़ आत्मीयता के प्रमाण हैं।

मुख्यमंत्री जी ने रेखांकित किया कि दिल्ली मेट्रो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और बुलेट ट्रेन जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में जापान सदैव भारत के साथ खड़ा रहा है। आज 1,400 जापानी कंपनियां भारत में कार्यरत हैं और यह साझेदारी अब सेमीकंडक्टर, एआई, ग्रीन हाइड्रोजन तथा क्रिटिकल मिनरल्स जैसे आधुनिक क्षेत्रों तक विस्तृत हो चुकी है। जापान की उन्नत तकनीक और भारत की युवा प्रतिभा का यह संगम वैश्विक स्तर पर नए आयाम स्थापित कर रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश और जापान के औद्योगिक संबंध तेजी से प्रगाढ़ हो रहे हैं। अपनी जापान यात्रा का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि यामानाशी प्रान्त के साथ ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है, इन्वेस्ट यूपी में यामानाशी डेस्क स्थापित की गई है तथा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्षेत्र में 500 एकड़ में 'जापानी सिटी' विकसित की जा रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जापान यदि 'लैंड ऑफ द राइजिंग सन' है, तो उत्तर प्रदेश 'लैंड ऑफ द सन डायनेस्टी' (सूर्यवंश) है, जहां भगवान बुद्ध से जुड़े प्रमुख तीर्थ स्थल भी स्थित हैं। वर्ष 2027 में दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और यह कॉरिडोर उस अमृत पर्व की प्रथम भेंट है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती अकी आबे ने मुख्यमंत्री जी को मेमोरियल गलियारे के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस कार्यक्रम के द्वारा मेरे पति को सम्मान दिया गया है। काशी और क्योटो दोनों शहरों का नाम 'क' अक्षर से शुरू होता है और दोनों प्राचीन शहर हैं। कन्वेंशन सेंटर की बाहरी दीवारों पर 108 संख्या में प्रतीकात्मक रुद्राक्ष लगाए गए हैं। 108 संख्या जापान के लोगों के लिए महत्वपूर्ण होती है। दिसम्बर माह के आखिरी दिन सभी जापानी बुद्ध मन्दिरों में 108 बार घण्टियाँ बजायी जाती हैं। इसके उपरान्त मुख्यमंत्री जी एवं श्रीमती अकी आबे ने प्रधानमंत्री जी के संवैधानिक दायित्वों के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित दो दिवसीय 'नमो बुक फेस्ट' का भी अवलोकन किया।

